श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

Demand to withhold disinvestment in NALCO

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी (नाल्को) न केवल उड़ीसा, बल्कि समूचे देश का गौरव है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मुनाफा करने वाला एक उपक्रम है। अगर इसे ढंग से चलाया जाएगा, तो यह और अधिक मुनाफा दे सकता है। इसमें पूंजी विनिवेश किए जाने के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। इस कम्पनी को गतवर्ष नवरत्न घोषित किया गया है, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस कम्पनी के CMD (चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर) के पद पर अभी भी स्थाई रूप से कोई व्यक्ति नहीं है। अभी भी कई निदेशक के पद रिक्त हैं। ये सब पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए। महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा के कोरापुट स्थित माइन्स एंड रिफाइनरी संयंत्र में गत अप्रैल में चुनाव के दौरान नक्सली हमले हुए। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को कहा जाए, कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक-ठाक करे। महोदय, अभी नाल्को का अंगुल स्थित CPP (कैपिटल पावर प्लांट) कोयले के गंभीर संकट पर गुजर रहा है। कोल इंडिया के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के ताल्चर फील्ड्स में पर्याप्त कोयला है। वहां पर पता नहीं चलता है कि इसमें हर साल कोयले का संकट क्यों दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इस सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसानग्रस्त करने हेतु कहीं न कहीं साजिश की जा रही है, ताकि धीरे-धीरे इससे पूंजी विनिवेश कर लिया जाएगा एवं बाद में इसे निजी क्षेत्र वाले खरीद लेंगे। अतः सरकार से मेरी यह मांग है कि वह इसके प्रति सतर्क रहे और नाल्को हमेशा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बना रहे। ऊपर से इसके दोनों प्लांट साइट अर्थात् अंगुल और कोरापुट के दामनजोड़ी के पास एल्युमिनियम पार्क बनाया जाए और एनसिलियेरीज़ उद्योग हेतु अवसर बनाया जाए। जल्द.0ी से जल्दी इसके विस्थापित की समस्या को हल कर दिया जाए। कम्पनी के अंदर और पैरिफेरी में रोज़गार के जो भी अवसर हैं, सब में लेस अफेक्टेड पीपल्स, यानी LAPs को भी मौका दिया जाए। कांट्रेक्टरों के नीचे जो भी हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, उन्हें एल्युमीनियम सेड्यूल के नाम से पैकेज दिया जाए। मेरी कुल मिलाकर यह मांग है कि नाल्को के सार्वजनिक क्षेत्र स्वरूप को कायम रखने हेतु भरपूर प्रयास किया जाए, न कि उससे पूंजी विनिवेश किया जाए।

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

Request for financial assistance to implement the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Andhra Pradesh

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government of India has introduced the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana with an aim to provide access to electricity to all households in the country in five years, that is, by 2010. Andhra Pradesh is front-runner. The outlay of RGGVY is Rs.781.76 crores for four APDISCOMs for electrification of 14,182 unelectrified habitations and 37,99,213 rural households including 24,99,213 BPL rural households in 22 districts.

Out of above, REC has accorded scheme sanctions for 17 districts for an amount of Rs.648.29 crores during the month of October, 2005. Schemes for balance five districts, that is, East Godavari, Medak, Ranga Reddy, Warangal and Karimnagar for an amount of Rs.133.62 crores are accepted in principle by REC but sanction is awaited. DISCOMSs have already spent an amount of Rs.49.51